



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 7, 2014/आषाढ़ 16, 1936

No. 346]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2014/ASHADHA 16, 1936

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2014

**सा.का.नि. 433(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 36 की उप-धारा (1) के अनुसरण में, उक्त संस्थान के व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से, उक्त अधिनियम की धारा 27 के अधीन बनाए गए राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान के प्रथम परिनियम का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रकाशित करती है, अर्थात् :—

2. (1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान परिनियम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त परिनियम कहा गया है) के परिनियम 3 के खंड 3.6 के “टिप्पण 2” का लोप किया जाएगा ।

4. उक्त परिनियम के परिनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित परिनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

6. नियुक्ति

6.1 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नियमित आधार पर नियुक्त करने को नीति अंगीकृत करता है ।

6.2 राष्ट्रीय औषध-शिक्षा और अनुसंधान संस्थान मोहाली के अनुमोदन से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून एक अधिकारी होगा, जो विद्यमान संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण का परीक्षण और सिफारिश पर विचार करेगी, के साथ-साथ निम्नलिखित कसौटियां होंगी :—

(i) जब विद्यमान संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है तो क्या निष्पक्ष और पारदर्शी रीति का पालन भर्ती की किसी नियमित पद्धति का पालन किया गया था ।

(ii) क्या उसका पूर्व अनुपालन और सेवा अभिलेख संतोषप्रद पाए गए थे ।

- (iii) क्या वह अपनी नियुक्ति के समय उक्त विशिष्ट पद के लिए दी गई अर्हताओं को पूर्ण करता है जब उसे नियमितिकरण के लिए विचार किया गया है ।

5. उक्त परिनियम में परिनियम 8 के खंड 8.2 में 'संविदाओं का' शब्दों का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 50020/16/2010-एनआईपीआईआर]

शंभू कालोलिकर, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—प्रथम परिनियम सा.का.नि. 391 तारीख 30 अक्टूबर, 2003।

## MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2014

**G.S.R. 433(E).**—In pursuance of sub-section (1) of Section 36 of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998, (13 of 1998), the Central Government hereby publishes the following further amendments to the first statutes of the National Institute of Pharmaceutical Education and Research made under Section 27 of the said Act by the Board of Governors of the said Institute with the previous approval of the Visitor, namely:—

2. (1) These Statutes may be called the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Statutes, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the National Institute of Pharmaceutical Education and Research Statutes (hereinafter referred to as the said Statutes), "Note 2" of clause 3.6 of Statute 3 shall be omitted.

4. In the said Statutes, for Statute 6, the following Statute shall be substituted, namely:—

#### 6. APPOINTMENTS

6.1 The NIPER adopts a policy of making appointments on regular basis.

6.2 A high level Committee may be constituted with the approval of NIPER, Mohali, including an officer not below the rank of Joint Secretary from the Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Pharmaceuticals) which will examine and recommend the regularisation of existing contractual employees taking into account, inter-alia, the following criteria:—

- (i) whether a regular method of recruitment was followed in a fair and transparent manner while appointing the existing contractual employee;
- (ii) whether his or her past performance and the service record have been found satisfactory;
- (iii) whether he or she fulfilled the qualification provided for that particular post at the time of his or her appointment on which he or she is being considered for regularisation.

5. In the said Statutes, in Statutes 8, in clause 8.2, the words "the contracts" shall be omitted.

[F. No. 50020/16/2010-NIPER]

SHAMBHU KALLOLIKAR, Jt. Secy.

**Footnote:**—The first Statutes were published vide number G.S.R.391, dated the 30th October, 2003.